मध्य प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

19. **चौ० हरि सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कितने जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया है ; और

(ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े इन जिलों में उद्योग स्थापित करने हेतु क्या सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित किए गए जिलों की संख्या 36 है ।

(ख) किसी राज्य के विशेष जिलों का औद्योगीकरण करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, तथापि, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार कई प्रोत्साहन देती है, जैसे केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में एककों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी में प्राथमिकता रियायती वित्त आदि । मध्य प्रदेश में सभी 36 जिले इन प्रोत्साहनों को पाने के पात्र हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने "उद्योग रहित जिला" आधारभूत विकास योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के लिए 6 विकास केन्द्र भी स्वीकृत किए हैं ।

कुटीर उद्योगों के विकास के संबंध में नीति

20. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिये हाल में कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने कुम्हारों और चमड़े का काम हाथ से करने वालों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो इन व्यवसायों में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं और उन्हें क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) सरकार की वर्तमान नीति कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर देना है । खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष 1990-91 के लिए 205 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । आठवीं योजना के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के संवर्धन को अधिक गांवों को सम्मिलित करके तेज किया जायेगा । खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न सुविधाएं मुहैया करता है जैसे कम ब्याज पर वित्तीय सहायता, ब्याज के लिए राज सहायता, खरीदारी में वरीयता, उत्पाद शुल्क में छूट, कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन संबंधी सहायता इत्यादि ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में चमड़ा तथा मिट्टी के बर्तन उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 2,93,324 तथा 3,53,853 है ।

Modernisation of Airports at Bombay and Delhi

21. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government are considering to award the Delhi and Bombay airport modernisation projects to a foreign consortium in view of the highly sophisticated nature of the job involving air safety;

(b) if so, what are the details of the allocations made in this behalf for the year 1990-91 and 1991-92; and

(c) by when this project will commence and what are the details of